

**आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांकी
देहरादून (उत्तराखण्ड)**

शुक्रवार 04.04.2025

समय 1830

मुख्य समाचार :-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 फीसदी केंद्र वित्त पोषण और 6 हजार 839 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के चौखुटिया में 'चैत्र अष्टमी मेले' का शुभारंभ किया, कहा— सरकार सुदूरवर्ती गांवों तक सड़क, पेयजल और शिक्षा पहुंचाने पर कार्य कर रही है।
- शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने तथा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
- और... उत्तराखंड में बारहमासी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता-2025' की शुरुआत की।

केंद्रीय मंत्रिमंडल

केंद्र सरकार ने सीमाओं पर बसे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। इसमें 6 हजार 839 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय आयेगा, जिसे शत-प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे ब्लॉक स्थित गांवों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करेगा।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 18 हजार 658 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1247 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।

सीएम चौखुटिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा के चौखुटिया में 'चैत्र अष्टमी मेले' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुदूरवर्ती गांवों तक सड़क, पेयजल और शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है। केदारखंड के विकास पर बोलते हुए श्री धामी ने कहा कि मानसखंड के मंदिरों का भी पुनरुद्धार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार लखपति दीदी योजना के अंतर्गत चौखुटिया और द्वारहाट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है।

वक्फ़ संशोधन विधेयक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ़ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित होने पर कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और न्यायिक सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ़ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे समाज के व्यापक हित में उपयोग किए जाएं।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के नींबूवाला का दौरा कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्युत लाइन के तारों को भूमिगत करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से निर्देश दिए। इसके अलावा श्री जोशी ने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता और गति बनाए रखने पर जोर दिया तथा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया।

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा ने पिथौरागढ़ जिले के आदर्श मत्स्य ग्राम डुंगरी में मानकों पर आधारित चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मानकों की उपयोगिता पर संवाद किया गया। कार्यक्रम में बीआईएस के क्षेत्रीय निदेशक सौरभ तिवारी ने दैनिक उपभोग के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद खरीदने की अपील की।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने तथा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। आज देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग और विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने राज्य के विद्यालयों में पुस्तकें उपलब्ध कराने तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता

उत्तराखण्ड की समृद्ध संस्कृति के प्रचार, बारहमासी पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए सरकार ने 'सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता-2025' की शुरुआत की है। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सरकार ने पहली बार इस पहल को शुरू किया है। है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से इस प्रतियोगिता में सक्रिय भूमिका निभाने और अपने रचनात्मक योगदान से उत्तराखण्ड को पर्यटन की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया है।

कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी itda.uk.gov.in/content-competition के माध्यम से भी प्रतिभाग कर सकते हैं।

प्लास्टिक से बनी बेंच

खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में प्लास्टिक से बनी बेंचों का लोकार्पण किया। इन बेंचों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने पानी की जो बोतले इस्तेमाल की थी, उन खाली बोतलों को रिसाइकिल करके यह बेंच बनाई गई है। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही तय किया था कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की तर्ज पर कराया जाएगा, इस दिशा में यह एक अहम कदम था।

उन्होंने कहा कि इस पहल ने देश दुनिया के लोगों को बताया है कि किस तरह पर्यावरण का संरक्षण रीसाइक्लिंग के जरिए किया जा सकता है।

वाइब्रेंट विलेज योजना

पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आईटीबीपी को स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और पलायन को रोकने के लिए उत्तराखण्ड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच यह महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते से भेड़-बकरी पालकों, कुक्कुट और मछली आपूर्ति से पशुपालकों को लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि यह समझौता सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री गोस्वामी ने पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए ताकि आईटीबीपी को स्थानीय और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

आदि कैलाश यात्रा

राज्य सरकार ने आगामी आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस महीने के अंत में यात्रा शुरू होने की संभावना है। इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन ने यात्रा मार्गों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि यात्रा मार्ग का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भेजी जा रही है।

हैलीकॉप्टर शटल सेवा

चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से बदरीनाथ—केदारनाथ मंदिर समिति ने आज देहरादून में हैलीकॉप्टर शटल सेवा और चार्टर हैली सेवा कम्पनियों के साथ चर्चा की। बैठक में हैली सेवा से आने वाले तीर्थयात्रियों का विवरण एक दिन पहले मंदिर समिति को उपलब्ध कराने समेत अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि यात्रा से पहले हैली कम्पनियों के साथ बैठक का उद्देश्य सभी आम तीर्थयात्रियों और हैली तीर्थयात्रियों के बीच समन्वय स्थापित करना और सरल व सुगम दर्शन सुनिश्चित करना है।